

	 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION Entrepreneur First	राजस्थान वित्त निगम Udyog Bhawan, Tilak Marg, JAIPUR Phone: 0141-2385513 Website : www.rfc.rajasthan.gov.in E mail: kkgupta@rfc.rajasthan.gov.in
---	---	---

(Credit Appraisal Section-1)

Ref.No.RFC/CAS-I/CPMD-12/ 409

Dated: 11.03.2020

C I R C U L A R
(CAS No. 50.)

Reg.: Compliance of the provisions of 'Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019.

The Government of Rajasthan has notified the Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Ordinance 2019. A copy of the Act & Rules are enclosed for ready reference.

All concerned are advised to make a note of it and ensure compliance.


(Urmila Rajoria)
Managing Director

Encl: As above.

Copy to:

1. All Branch Offices.
2. Standard Circulation at HO.
3. DGM(MS) for hoisting on RFC Website.

65

**Government of Rajasthan
Department of Industries, M.S.M.E, DMIC,
State Enterprises & NRIs**

Sub: Compliance of the provisions of 'Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019

You are aware that the Government in an attempt to encourage hassle free establishment of Micro, Small and Medium enterprises, had notified the 'Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Ordinance 2019 on 4th March 2019 and its rules on 24.5.2019. The Ordinance was subsequently enacted on 17th July, 2019. Copy of the Act and Rules is enclosed for reference.

2. Subject to provisions of the said Act and the rules made there under, the MSME units are entitled for exemption from approvals and inspections under any Rajasthan law for a period of 3 years from the date of issuance of the Acknowledgement Certificate and after the expiry of the said period of three years the enterprise shall have to obtain required approvals within six months from the date of such expiry.
3. To avail the benefits of the Act, the enterprise is required to file 'Declaration of Intent' online to the Nodal Agency (BIP) on rajudyogmitra portal (<https://rajudyogmitra.rajasthan.gov.in/>). An auto generated online 'Acknowledgement Certificate' is issued to the enterprise instantly. The enterprise can download the Acknowledgement Certificate from their respective application dashboard.
4. The Bureau of Investment Promotion and District Industries Centre are the State Level and District Level Nodal Agencies respectively, for purpose of the Act.
5. One day Workshops were organized during the month of Nov-Dec, 2019 at the Divisional Head Quarter/District Headquarter to publicise the initiatives of the GoR including the MSME Act. It has been observed that some of the district level authorities concerned with approvals of the business enterprises are not aware about the abovementioned provisions of the Act and hence are not complying with its provisions.

MD 538
7.2.20

ED 03

07-02-2020

6. You are therefore requested to direct the departments/offices under your jurisdiction at the Head Quarter and District level ensuring that the provisions of the Act are fully complied with so that the enterprises which are establishing their units in accordance with the provisions of the Act & Rules and have valid Acknowledgement Certificate are not bothered for inspections and taking approvals, up to a period of 3 yrs. and 6 months. The sso ids of the concerned officers in relation to the MSME Act may be shared via email to bip.raj@nic.in for mapping these on the portal and for providing viewing rights.

Subodh
29/01
(Dr. Subodh Agarwal)

Addl. Chief Secretary, Industries

Encl: a/a

1. Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary
2. ~~Commissioner / CMD / MD / Registrar / Director / Inspector General~~ (as per list enclosed) R F C

U.O. Note No : BIP/MSME/923
Jaipur date : 05-2-2020

ED

GM/1057
07/2/20
GM(D)

DGM(CAS)

3

7/2/2020

13/2/2020

Am (CAS)
Pl-put up file

10/2

(Sd) 11/2/20



राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

आषाढ 27, गुरुवार शाके 1941-जुलाई 18, 2019
Asadha 27, Thursday, Saka 1941-July 18, 2019

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 17, 2019

संख्या प.2(24)विधि/2/2019.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 जुलाई, 2019 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम, 2019
(2019 का अधिनियम संख्यांक 14)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 जुलाई, 2019 को प्राप्त हुई)

राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना और प्रवर्तन के लिए कतिपय अनुमोदनों और निरीक्षणों से छूट के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।

यतः, समावेशी आर्थिक वृद्धि और नियोजन सृजन के संवर्धन की दृष्टि से, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान देना और उद्यमिता का संवर्धन करना राज्य का लक्ष्य है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना और प्रवर्तन के लिए अपेक्षित कतिपय अनुमोदनों और निरीक्षणों से छूट को प्रभावी करना समीचीन है;

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम, 2019 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह 4 मार्च, 2019 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र" से धारा 5 के अधीन जारी किया गया अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ख) "अनुमोदन" से राजस्थान राज्य में किसी उद्यम की स्थापना या प्रवर्तन के संबंध में किसी राजस्थान विधि के अधीन अपेक्षित कोई अनुज्ञा, अनापत्ति, अनुज्ञापन, सहमति, अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञप्ति इत्यादि अभिप्रेत है;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से सरकार का कोई विभाग या एजेंसी या कोई स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय, राज्य के स्वामित्वाधीन निगम, पंचायती राज संस्था, नगरपालिका, नगर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास या किसी राजस्थान विधि द्वारा या उसके अधीन या सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन गठित या स्थापित कोई भी अन्य प्राधिकारी या एजेंसी, जिसको राज्य में किसी उद्यम की स्थापना या प्रवर्तन के लिए अनुमोदन मंजूर या जारी करने के लिए शक्तियां या उत्तरदायित्व न्यस्त किये गये हैं, अभिप्रेत है;

(घ) "जिला सशक्त समिति (जि.स.स.)" से राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 7) की धारा 3 के अधीन गठित जिला सशक्त समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "उद्यम" से कोई सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" से राजस्थान राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम" से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 27), समय-समय पर यथासंशोधित, में यथापरिभाषित सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम अभिप्रेत है;

(ज) "नोडल एजेंसी" से धारा 3 में निर्दिष्ट नोडल एजेंसी अभिप्रेत है;

(झ) "अधिसूचना" से राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और शब्द 'अधिसूचित' का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है; और

(ठ) "राज्य सशक्त समिति (रा.स.स.)" से राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 7) की धारा 3 के अधीन गठित राज्य सशक्त समिति अभिप्रेत है।

3. नोडल एजेंसी.- (1) सरकार और राज्य सशक्त समिति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, विनिधान संवर्धन ब्यूरो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी होगा।

(2) सरकार और जिला सशक्त समिति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, जिला उद्योग केन्द्र इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए जिला स्तरीय नोडल एजेंसी होगा।

4. नोडल एजेंसियों की शक्तियां और कृत्य.- (1) सरकार के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, नोडल एजेंसियों की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) राज्य में उद्यमों की स्थापना में सहायता करना और उसे सुकर बनाना; और

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त आशय की घोषणा और जारी किये गये अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र का अभिलेख संधारिबु करना।

(2) सरकार, नोडल एजेंसियों को ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य समनुदेशित कर सकेगी जैसेकि वह इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए ठीक समझे।

5. घोषणा का फाइल किया जाना.- (1) कोई व्यक्ति जो कोई उद्यम आरंभ करने का आशय रखता है, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को उद्यम आरंभ करने के आशय की घोषणा, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, दे सकेगा।

स्पष्टीकरण.- कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व, धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित समस्त अनुमोदनों या उनमें से किसी अनुमोदन को अभिप्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया है, वह इस उप-धारा के अधीन कोई उद्यम आरंभ करने के आशय की घोषणा देने का विकल्प भी दे सकेगा।

(2) सभी प्रकार से पूर्ण घोषणा की प्राप्ति पर, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी उस व्यक्ति को, जिसने उप-धारा (1) के अधीन घोषणा दी है, विहित प्ररूप में, तत्काल अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र जारी करेगी।

6. अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र का प्रभाव.- (1) धारा 5 के अधीन जारी किया गया अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र, सभी प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रभावी होगा मानो वह इसके जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए, धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित कोई अनुमोदन हो और तीन वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, उस उद्यम को ऐसी समाप्ति की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित अपेक्षित अनुमोदन अभिप्राप्त करने होंगे:

परन्तु अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र, किसी व्यक्ति को मास्टर योजना, जहां कहीं भी ऐसी योजना प्रवृत्त है, में विनिर्दिष्ट भूमि-उपयोग से भिन्न किसी भूमि-उपयोग का हकदार नहीं बनायेगा। यह किसी व्यक्ति को राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) की धारा 16 में यथाविनिर्दिष्ट निर्बंधित प्रवर्ग अर्थात् चरागाह भूमि, जलाशय आदि के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग करने का भी हकदार नहीं बनायेगा।

(2) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट तीन वर्ष की कालावधि के दौरान, कोई भी सक्षम प्राधिकारी धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित किसी अनुमोदन के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में कोई निरीक्षण नहीं करेगा।

7. छूट.- जहां सरकार या उसके अधीन कोई प्राधिकारी, किसी उद्यम को किसी भी अनुमोदन या निरीक्षण या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उससे संबंधित किन्हीं उपबंधों से छूट देने के लिए सशक्त है वहां सरकार या, यथास्थिति, ऐसा कोई प्राधिकारी, ऐसे केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य में स्थापित किसी उद्यम को, धारा 5 के अधीन अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किये जाने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की कालावधि के लिए, ऐसी छूट देने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

8. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- सरकार या नोडल एजेंसी या सक्षम प्राधिकारी अथवा सरकार, नोडल एजेंसी या सक्षम प्राधिकारी के किसी कर्मचारी के विरुद्ध, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

9. अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना.- (1) इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राजस्थान विधि में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होने पर भी, प्रभावी होंगे।

(2) विशिष्टतया और इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपबंध, निम्नलिखित अधिनियमितियों में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे और इन अधिनियमितियों के उपबंध इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप संशोधित रूप में पढ़े जायेंगे, अर्थात्:-

- (क) राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3);
- (ख) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15);
- (ग) राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35);
- (घ) राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम सं. 12);
- (ङ) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25);
- (च) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13);
- (छ) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18);
- (ज) जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2); और
- (झ) अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 39)।

10. व्यावृत्तियां.- धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि किसी उद्यम को, इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित सीमा तक के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के लागू होने से या तदधीन विहित किन्हीं विनियमकारी अध्याप्यों और मानकों से छूट दी गयी है।

11. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

12. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे जाते हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधानमण्डल का सदन ऐसे किन्हीं नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

13. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश सं. 1) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी और राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, July 17, 2019

No. F. 2 (24) Vidhi/2/2019.- In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Sookshma, Laghu Aur Madhyam Udhyaam (Sthapana Aur Pravartan Ka Sukarikaran) Adhiniyam, 2019 (2019 Ka Adhiniyam Sankhyank 14):-

(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(FACILITATION OF ESTABLISHMENT AND OPERATION) ACT, 2019
(Act No. 14 of 2019)

(Received the assent of the Governor on the 17th day of July, 2019)

An
Act

to provide for exemption from certain approvals and inspections for establishment and operation of the micro, small and medium enterprises in Rajasthan and matters connected therewith or incidental thereto.

Whereas, with a view to promote inclusive economic growth and employment generation, the State aims to address the specific needs of the micro, small and medium enterprises and promote entrepreneurship, it is expedient to give effect to exemption from certain approvals and inspections required for establishment and operation of micro, small and medium enterprises;

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall be deemed to have come into force on and from 4th March, 2019.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Acknowledgment Certificate" means the acknowledgment certificate issued under section 5;

(b) "approval" means any permission, no-objection, clearance, consent, approval, registration, licence and the like, required under any Rajasthan Law in connection with the establishment or operation of an enterprise in the State of Rajasthan;

(c) "Competent Authority" means any department or agency of the Government or a local authority, statutory body, State owned corporation, Panchayati Raj Institution, Municipality, Urban Development Authorities, Urban Improvement trust or any other authority or agency constituted or established by or under any Rajasthan Law or under administrative control of the Government, which is entrusted with the powers or responsibilities to grant or issue approval for establishment or operation of an enterprise in the State;

(d) "District Empowered Committee (DEC)" means the District Empowered Committee constituted under section 3 of the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Act, 2011 (Act No. 7 of 2011);

(e) "enterprise" means a micro, small or medium enterprise;

(f) "Government" means the State Government of Rajasthan;

(g) "micro, small or medium enterprise" means the Micro, Small or Medium Enterprises, as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Central Act No. 27 of 2006), as amended from time to time;

(h) "nodal agency" means the nodal agency referred to in section 3;

(i) "notification" means a notification published in the Rajasthan Gazette and the word 'notified' shall be construed accordingly;

(j) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

(k) "State" means the State of Rajasthan; and

(l) "State Empowered Committee (SEC)" means the State Empowered Committee constituted under section 3 of the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Act, 2011 (Act No. 7 of 2011).

3. Nodal Agency.-(1) Subject to superintendence, direction and control of the Government and the State Empowered Committee, Bureau of Investment Promotion shall be the State level Nodal Agency for the purpose of this Act.

(2) Subject to superintendence, direction and control of the Government and the District Empowered Committee, District Industries Centre shall be the District level Nodal Agency for the purpose of this Act.

4. Powers and functions of nodal agencies.- (1) Subject to the superintendence, direction and control of the Government, the powers and functions of the nodal agencies shall be as follows: -

(a) to assist and facilitate establishment of enterprises in the State; and

(b) to maintain the record of Declaration of Intent received and Acknowledgement Certificate issued under this Act.

(2) The Government may assign such other powers and functions to the nodal agencies as it may deem fit for giving effect to the provisions of this Act.

5. Filing of Declaration.- (1) Any person who intends to start an enterprise may furnish to the State level nodal agency a declaration of intent to start an enterprise in such form and in such manner as may be prescribed.

Explanation.- Any person who has moved the Competent Authority to so obtain all or any of the approvals as defined in clause (b) of section 2 before the commencement of this Act may also opt to furnish Declaration of Intent to start an enterprise under this sub-section.

(2) On receipt of a declaration completed in all respects, the State level nodal agency shall, forthwith, issue an Acknowledgement Certificate in the prescribed form, to the person who furnished the declaration under sub-section (1).

6. Effect of the Acknowledgement Certificate.- (1) An Acknowledgement Certificate issued under section 5 shall, for all purposes, have effect as if it is an approval as defined in clause (b) of section 2, for a period of three years from the date of its issuance and after the expiry of the said period of three years, the enterprise shall have to obtain required approvals as defined in clause (b) of section 2 within six months from the date of such expiry:

Provided that the Acknowledgement Certificate shall not entitle a person to use a land in deviation to the land use specified in the master plan wherever such plan is in force. It shall also not entitle a person to use the land falling in restricted category namely pasture land, water body, etc. as specified in section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No.3 of 1955).

(2) During the period of three years specified in sub-section (1), no competent authority shall undertake any inspection for the purpose of, or in connection with, any approval as defined in clause (b) of section 2.

7. Exemption.- Where the Government or any authority under it is empowered to exempt any enterprises from any approval or inspection or any provisions relating thereto under any Central Act, the Government or, as the case may be, any such authority shall, subject to the provisions of such Central Act, exercise such powers to grant such exemption to an enterprise established in the State for at least a period of three years from the date of issue of the Acknowledgement Certificate under section 5.

8. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or Nodal Agency or Competent Authority or any employee of the Government, Nodal Agency or Competent Authority for anything which, in good faith, is done or intended to be done under this Act or any rules made thereunder.

9. Act to override other laws.—(1) The provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other Rajasthan law, for the time being in force.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions of this Act, such provisions shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the following enactments and the provisions of these enactments shall be read as amended in conformity with the provisions of this Act, namely:—

- (a) Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955);
- (b) Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956);
- (c) Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959);
- (d) Rajasthan Gramdan Act, 1971 (Act No. 12 of 1971);
- (e) Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982);
- (f) Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994);
- (g) Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009);
- (h) Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009); and
- (i) Ajmer Development Authority Act, 2013 (Act No. 39 of 2013).

10. Savings.— Subject to the provisions of section 7, nothing in this Act shall be construed as exempting any enterprise from the application of the provisions of any law for the time being in force, or any regulatory measures and standards prescribed thereunder, except to the extent expressly provided in this Act.

11. Power to remove difficulties.— (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order under this section shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature.

12. Power to make rules.— (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such

modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

13. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 1 of 2019) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal and without prejudice to the provisions of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955), all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

महावीर प्रसाद शर्मा,

Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

7)

**Government of Rajasthan
Industries (GR-I) Department**

File No. F.5(16)Industries/I/2019

Jaipur, Date: 24.05.2019

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 12 of the Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 01 of 2019), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Acknowledgment Certificate" means the Acknowledgment Certificate issued under section 5 of the Ordinance;
 - (b) "Authorized Officer" means person authorized by State Level Nodal Agency for carrying out the functions assigned in these rules;
 - (c) "Commencement of Commercial Operation" means the date on which the enterprise issues the first bill of supply/ invoice/tax invoice, of the goods manufactured or services rendered relating to Declaration of Intent furnished under these rules;
 - (d) "Declaration of Intent" means Form, either in physical or electronic format, for furnishing the information by the enterprise under section 5 of the Ordinance;
 - (e) "Enterprise" means micro, small or medium enterprise;
 - (f) "Form" means the form appended to these rules;
 - (g) "Micro, small or medium enterprise" means a micro, small or medium enterprise, as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Central Act No. 27 of 2006), as amended from time to time;
 - (h) "New enterprise" means a new micro, small or medium enterprise whose date of commencement of commercial operation is on or after the date of promulgation of the Ordinance i.e. March 04, 2019 and includes an enterprise set up or proposed to be set up by an existing enterprise for manufacturing products or providing services at a location which is separately identifiable and different from location of the existing enterprise;

(i) "Ordinance" means the Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Ordinance, 2019;

(j) "Section" means a section of the Ordinance; and

(k) "State Empowered Committee (SEC)" means the State Empowered Committee constituted under section 3 of the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Act, 2011 (Act No. 7 of 2011).

(2) Word or expression used but not defined in these rules, shall have the same meaning as assigned to them in the Ordinance.

3. Procedure for Grant of Acknowledgment Certificate.- (1) Every new enterprise seeking Acknowledgment Certificate under the Ordinance shall furnish a duly filled Declaration of Intent to the State Level Nodal Agency in Form-I, electronically on the portal. However, in case of special circumstances or failure of electronic system due to unforeseen circumstances, the enterprise may submit Declaration of Intent, in physical format to the State Level Nodal Agency.

(2) On the receipt of Declaration of Intent, the Acknowledgment Certificate shall be granted in electronic format by the State Level Nodal Agency in Form-II, stating the date of receipt of Declaration of Intent and the period of validity of Acknowledgment Certificate.

(3) In case the Declaration of Intent is submitted to State Level Nodal Agency in physical format as specified in sub-rule (1), the State Level Nodal Agency shall issue the Acknowledgment Certificate in Form-II in physical format.

(4) The Declaration of Intent shall be submitted by,-

(a) the managing partner, in case of proprietary enterprise;

(b) the authorized partner in case of partnership enterprise; and

(c) the authorized person in case of other forms of enterprises.

(5) In case the enterprise is having commercial operations on more than one set of premises, a separate Declaration of Intent shall be submitted for each such set of premises.

4. Functions of The State Level Nodal Agency.- (1) The State Level Nodal Agency shall act as the coordinating and implementing agency for carrying out the purposes of the Ordinance.

(2) The State Level Nodal Agency shall appoint one or more Authorized Officer in the Bureau of Investment Promotion for the purpose of issuance of Acknowledgment Certificate under the Ordinance.

(3) The State Level Nodal Agency shall receive and address the grievances and queries of enterprise related to the Ordinance and these rules.

72

(4) The State Level Nodal Agency shall maintain the electronic portal for carrying out the purposes of the Ordinance and keep record of Declaration of Intent and the Acknowledgment Certificate.

(5) State Level Nodal Agency shall, on issuance of Acknowledgment Certificate, forward the Declaration of Intent and the Acknowledgment Certificate of enterprise to all Competent Authorities.

(6) State Level Nodal Agency shall be responsible for coordination between the Competent Authority and enterprise. In case of dispute between enterprise and Competent Authority, State Level Nodal Agency shall resolve the dispute and may seek directions from the State Empowered Committee, as and when required.

5. Removal of doubts.- If any difficulty arises in the application or interpretation of the Ordinance and these rules, the matter shall be referred by the State Level Nodal Agency to the State Empowered Committee whose decision thereon shall be final, in such matters.

FORM-I

(See rule 3 (1))

Declaration of Intent

{Under the Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Ordinance, 2019 }

Details of Applicant	
Name of Applicant	
Aadhaar Number of applicant	
Gender Male/Female/Others	
Social Category General/SC/ST/OBC/Others	
Correspondence address & contact details of Enterprise	
Address	
Plot No /Khasra no/House No.	
Name of premise/building	
Road/Street/Lane	
Landmark	
Area/ Locality	
State	
District	
Classification of Geographical Area (Rural/ Urban)	
Tehsil	
Village/Town/City	
PIN Code	
Contact Details	

Mobile Number	
Alternate Mobile Number	
Telephone	
Email Id	
Enterprise Information	
Name of the Undertaking/Enterprise	
PAN Number	
Major Activity of Enterprise (Manufacturing/Service)	
Products to be Manufactured/Services to be provided	
Category of Enterprise (Micro/ Small/ Medium)	
Type of Organization (Proprietary/Hindu Undivided Family (HUF)/Partnership/Co-operative/ Private Limited/Public Limited/ LLP/Self-help group/Others)	
Location of Manufacturing/Service Activity of Enterprise	
Plot No /Khasra no/House No.	
Name of premise/building	
Road/Street/Lane	
Landmark	
Area/ Locality	
Classification of Geographical Area (Rural/Urban)	
District	
Tehsil	
Village/Town/City	
PIN Code	
Declaration	
I.....residing at state that I am authorized signatory for M/s, and hereby give the following declaration and undertake that :- (i) I/We certify that the information furnished in Declaration of Intent under the Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprise (Facilitation of Establishment and Operation) Ordinance 2019 and the rules made there under is true, correct and complete to the best of my/our knowledge & belief and no material information has been concealed. (ii) I/We have read the Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprise (Facilitation of Establishment and Operation) Ordinance, 2019 and the rules made there under and undertake to abide by them. In case of changes in above details, the same will be intimated to the Nodal agency at the earliest. (iii) I/We are furnishing the Declaration of Intent for the enterprise which is a new enterprise as per definition provided the Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprise (Facilitation of Establishment and Operation) Rules, 2019. (iv) I/We have not previously availed the Acknowledgement certificate for the land or building	

	or premises as mentioned in 'Location of Manufacturing/Service Activity of Enterprise' in Declaration of Intent.
(v)	I/We will maintain the safety standards in operation of the enterprise to ensure safety and health of the workers or employees.
(vi)	I/We will not engage in any manufacturing or service activity which is prohibited under any law or which may pose serious threat to public health or law and order.
Date	
Place	
Name	
Designation	

FORM-II

(See rule 3(2) and 3(2))

Acknowledgment Certificate

M/S has filed a Declaration of Intent under the Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Ordinance, 2019 to set up a (Manufacturing/Service) enterprise. The receipt of the Declaration of Intent for the enterprise is hereby acknowledged with following details

Acknowledgment Details	
Acknowledgment Number	
Date of Acknowledgment	
Validity of Acknowledgment	
Name of the Enterprise	
Type of Organization	
Official Address of Enterprise	
Location of Manufacturing/Service Activity of Enterprise	
Category of Enterprise	
Major Activity of Enterprise	
Product(s) to be Manufactured/Service(s) to be provided	

- The Acknowledgement Certificate is issued under the provisions of section 5 of the said Ordinance.
- Subject to provisions of the said Ordinance and the rules made there under, it entitles the enterprise:
 - Exemption from approval under any Rajasthan Law.

- (b) Exemption from inspection for the purpose of, or in connection with, any approval under any Rajasthan Law.
- (c) Exemption from approval and inspection, in case of exemption granted under section 7 of the Ordinance is applicable.
- (d) It can be presented to any Competent Authority or Bank or Financial Institution as and when required who shall treat it as valid approval as defined in clause (b) of section 2 of the Ordinance for all the purposes.

3. This Acknowledgement Certificate is issued, subject to following conditions:

- (i) The provisions of the Rajasthan Micro, Small, and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Ordinance, 2019 and its applicability shall be limited to land or building or premises and the activities mentioned in the Acknowledgement Certificate.
- (ii) After the expiry of Acknowledgment Certificate, the enterprise shall have to obtain required approvals, for which no further intimation shall be provided.
- (iii) In case of willful submission of wrong information in Declaration of Intent or breach or contravention of any of the provisions mentioned anywhere in the Ordinance & the rules made there under, the Acknowledgement Certificate will be revoked as per provisions of the Ordinance and rules made there under.
- (iv) The Acknowledgment Certificate will become void for the enterprise if it ceases to exist due to merger or split or demerger or acquisition or amalgamation of the enterprises or if it ceases to be a Micro, small or medium enterprise.

Nodal Agency: Bureau of Investment Promotion
Address: Bureau of Investment Promotion,
Udhyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur 302005

By Order of the Governor.

-sd-

(Neetu Barupal),

Dy. Secretary to the Government

74

Copy forwarded to the following for information and necessary action :-

1. Superintendent, Government Central Press, Jaipur along with a soft copy in CD for publication of this order in today's extra ordinary Gazette. It is requested that 10 copies of this order may be sent to this Department and 20 copies with bill may be sent to Commissioner, Industries, Rajasthan, Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur. Please ensure that soft copy in CD is same as hard copy provided to you for publication.
2. Pr. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan.
3. SA to Hon'ble Industries Minister, Rajasthan, Jaipur.
4. Sr. DS to Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur.
5. PS to ACS, Industries, Rajasthan, Jaipur.
6. PS to ACS, Finance, Rajasthan, Jaipur.
7. PS to Principal Secretary, Revenue, Rajasthan, Jaipur.
8. Ps to Principal Secretary, UDH Department, Rajasthan, Jaipur.
9. PS to Principal Secretary PHED, Rajasthan, Jaipur.
10. PS to Principal Secretary, Tourism, Rajasthan, Jaipur.
11. PS to Principal Secretary, Energy, Rajasthan, Jaipur.
12. PS to Secretary Local Self Government, Rajasthan, Jaipur.
13. PS to Secretary Labor, Rajasthan, Jaipur.
14. PS to Managing Director, RIICO Ltd., Jaipur.
15. PS to Secretary Finance (Revenue), Rajasthan, Jaipur.
16. PS to Chairman Managing Director, Vidyut Vitran Nigam Ltd., Jaipur, Jodhpur & Ajmer.
17. PS to Secretary, Rajasthan Pollution Control Board, Rajasthan, Jaipur.
18. PS to Commissioner, Industries, Rajasthan, Jaipur.
19. PS to Commissioner, Commercial Taxes Department, Rajasthan, Jaipur.
20. Ps to Commissioner, Jaipur Development Authority, Jaipur.
21. PS to Commissioner, BIP, Rajasthan, Jaipur.
22. Shri Sanjeev Saxena, Nodal Officer IT, Industries Department, Jaipur.
23. Guard file.


Dy. Secretary to the Government

75

LIST OF CONCERNED DEPARTMENTS

S.N	DESIGNATION
1	ADDITIONAL CHIEF SECRETARY, TRANSPORT DEPARTMENT
2	ADDITIONAL CHIEF SECRETARY, PUBLIC WORKS DEPARTMENT,
3	CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR, RAJASTHAN STATE WAREHOUSING CORPORATION
4	ADDITIONAL CHIEF SECRETARY, RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ
5	ADDITIONAL CHIEF SECRETARY, FINANCE
6	ADDITIONAL CHIEF SECRETARY, MEDICAL & HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT
7	PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT, REVENUE, COLONISATION,
8	PRINCIPAL SECRETARY INFORMATION TECHNOLOGY & COMMUNICATION DEPARTMENT
9	MANAGING DIRECTOR, RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION
10	PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT, PUBLIC HEALTH & ENGINEERING AND GROUND WATER DEPARTMENT,
11	PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT, FOREST & ENVIRONMENT, TOURISM, ART & CULTURE DEPARTMENT, RAJASTHAN
12	PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT, AGRICULTURE AND HORTICULTURE DEPARTMENT, RAJASTHAN
13	PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT, URBAN DEVELOPMENT & HOUSING DEPARTMENT
14	PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT, ENERGY DEPARTMENT AND CHAIRMAN, DISCOM, JAIPUR
15	SECRETARY TO GOVERNMENT, MINES AND PETROLEUM DEPARTMENT, RAJASTHAN, JAIPUR
16	SECRETARY TO GOVERNMENT, TRANSPORT DEPARTMENT & COMMISSIONER, TRANSPORT DEPARTMENT, RAJASTHAN
17	SECRETARY TO GOVERNMENT, WATER RESOURCES DEPARTMENT
18	SECRETARY TO GOVERNMENT, AYURVED & INDIAN MEDICINE DEPARTMENT, RAJASTHAN,
19	SECRETARY TO GOVERNMENT, MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT, RAJASTHAN
20	COMMISSIONER, JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY,
21	SECRETARY TO GOVERNMENT, LOCAL SELF GOVERNMENT AND GAD, CABINET, ESTATE, STATE MOTOR GARAGE & CIVIL AVIATION
22	SECRETARY TO GOVERNMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT, RAJASTHAN,
23	SECRETARY TO GOVERNMENT, SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
24	SECRETARY TO GOVERNMENT, LABOUR,

	EMPLOYMENT, SKILL & ENTREPRENEURSHIP, FACTORY & BOILER INSPECTION
25	SECRETARY TO GOVERNMENT, HOME DEPARTMENT
26	MANAGING DIRECTOR, RIICO,
27	SECRETARY TO GOVERNMENT, FINANCE (REVENUE) DEPARTMENT,
28	SECRETARY TO GOVERNMENT, HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT
29	COMMISSIONER, COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT, RAJASTHAN
30	REGISTRAR, COOPERATIVE DEPARTMENT
31	SECRETARY TO GOVERNMENT, FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
32	MANAGING DIRECTOR, RAJASTHAN STATE MINES AND MINERALS NIGAM LIMITED,
33	MANAGING DIRECTOR, RAJASTHAN RENEWABLE ENERGY CORPORATION LIMITED,
34	SECRETARY TO GOVERNMENT, ANIMAL HUSBANDARY, FISHERIES & GOPALAN DEPARTMENT,
35	COMMISSIONER, LABOUR DEPARTMENT AND MANAGING DIRECTOR, RAJASTHAN SKILL & LIVELIHOODS DEVELOPMENT CORPORATION (R.S.L.D.C.),
36	CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR, RAJSICO,
37	COMMISSIONER, COLLEGE EDUCATION & SPECIAL SECRETARY TO GOVERNMENT, HIGHER EDUCATION DEPARTMENT, RAJASTHAN
38	COMMISSIONER, E.G.S. AND DIRECTOR, SANITATION, PANCHAYATI RAJ & LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT, RAJASTHAN
39	MANAGING DIRECTOR, RAJASTHAN MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED
40	DIRECTOR, MINES AND GEOLOGY DEPARTMENT, UDAIPUR
41	MANAGING DIRECTOR, RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION,
42	COMMISSIONER, EXCISE DEPARTMENT
43	COMMISSIONER, RAJASTHAN HOUSING BOARD
44	INSPECTOR GENERAL, REGISTRATION & STAMPS
45	DIRECTOR GENERAL OF POLICE, RAJASTHAN, JAIPUR

Government of Rajasthan

Administrative Reform and Coordination (Gr-1) Department

Secretaries in-charge of Districts

S.N	District	Name	Designation & Department
1.	Ajmer	Sh. Bhawani Singh Detha	Secretary, LSG
2.	Alwar	Sh. Bhaskar A. Sawant	Pr. Secretary, UDH
3.	Bharatpur	Sh. Rohit Kumar Singh	ACS, Medical & Health and Family Welfare
4.	Bhilwara	Sh. Kunji Lal Meena	Pr. Secretary, Energy
5.	Bikaner	Dr. R. Venkateswaran	Pr. Secretary, Administrative Reforms and Coordination
6.	Bundi	Smt. Mugdha Sinha	Secretary, Science and Technology
7.	Baran	Sh. Rajesh Sharma	Secretary, Animal Husbandry and Fisheries
8.	Banswara	Sh. Akhil Arora	Pr. Secretary, Social Justice and Empowerment
9.	Barmer	Dr. Veena Pradhan	Commissioner, Child Empowerment
10.	Churu	Dr. Niraj Kumar Pawan	Registrar, Cooperative
11.	Chittorgarh	Sh. Sanjay Malhotra	Pr. Secretary, Revenue, Colonisation and Sainik Kalyan
12.	Dungarpur	Sh. Vikas Sitaramji Bhale	Divisional Commissioner, Udaipur
13.	Dholpur	Smt. Shuchi Sharma	Secretary, Higher and Technical Education
14.	Dausa	Smt. Gayatri A. Rathore	Secretary, Ayurved
15.	Sri Ganganagar	Sh. Vaibhav Galriya	Secretary, Medical Education
16.	Hanumangarh	Sh. Alok Gupta	Secretary, Devasthan
17.	Jhalawar	Sh. Rajash Kumar Yadav	Secretary, Transport
18.	Jaipur	Dr. Subodh Agarwal	ACS, Industries
19.	Jodhpur	Sh. Naveen Mahajan	Secretary, Water Resources
20.	Jalore	Sh. Ashutosh A.T. Pednekar	MD, RIICO
21.	Jhunjhunu	Sh. Alok	MD, RSRTC

22.	Jaisalmer	Dr. Krishna Kant Pathak	Secretary, Women and Child Development
23.	Kota	Sh. Pawan Kumar Goyal	CMD, Rajasthan State Warehousing Corporation
24.	Karauli	Sh. Ashwini Bhagat	Director, HCM, RIPA
25.	Nagaur	Sh. Naresh Pal Gangwar	Pr. Secretary, Agriculture and Horticulture
26.	Pali	Dr. Pritam B. Yashvant	Commissioner, CCT
27.	Pratapgarh	Sh. Naveen Jain	Secretary, Labour
28.	Sikar	Sh. Subir Kumar	Secy. to Hon'ble Governor
29.	Sirohi	Sh. Siddharth Mahajan	Secretary, Food and Civil Supplies
30.	Sawai Madhopur	Smt. Sreya Guha	Pr. Secy. Forest and Environment
31.	Rajsamand	Smt. Aparna Arora	Pr. Secretary, Minority Affairs
32.	Tonk	Sh. Sandeep Verma	Pr. Secy. PHED
33.	Udaipur	Sh. Abhay Kumar	Pr. Secretary, Planning

24/12/2020

(D) WY

RFC

(41)